भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 628

26 जुलाई, 2024 को उत्तर के लिए

इस्पात की मांग और उत्पादन

628. श्री ईरण्ण कडाडी:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान देश में उत्पादित इस्पात की कुल मात्रा कितनी है तथा वैश्विक उत्पादन में इसकी कितनी हिस्सेदारी है;

(ख) इस्पात की वर्तमान घरेलू मांग कितनी है तथा कुल वैश्विक इस्पात निर्यात में देश की कितनी हिस्सेदारी है; और

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान देश को वैश्विक स्तर पर इस्पात का शीर्षतम उत्पादक बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रभावी उपाय किए गए हैं?

उत्तर

इस्पात मंत्री **(श्री एच.डी. कुमारास्वामी)**

(क) भारत द्वारा क्रूड इस्पात के उत्पादन और वैश्विक उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी के साथ वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन (डब्ल्यूएसए) द्वारा वर्ष 2022 और 2023 के लिए जारी अनंतिम आंकड़े नीचे दिए गए हैं।

वर्ष	क्रूड इस्पात का उत्पादन (एमटी)		
	विश्व*	भारत#	भारत का शेयर%*
2022	1890.2	125.4	6.6
2023	1892.2	140.8	7.4
स्रोत: *वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन (डब्ल्यूएसए); #संयुक्त संयंत्र समिति एमटी=मिलियन टन; *अनंतिम			

(ख) वर्ष 2023-24 और अप्रैल-जून 2024 (अनंतिम) के दौरान भारत में तैयार इस्पात की खपत के आंकड़े नीचे दिए गए हैं:-

जारी....2/-

वर्ष	तैयार इस्पात खपत (मिश्रधातु/स्टेनलेस + गैर-मिश्रधातु) (एमटी में)
2023-24	136.29
अप्रैल-जून 2024-25*	35.42
स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति; *अनंतिम	

वर्ष 2023 के दौरान भारत द्वारा इस्पात निर्यात के साथ-साथ विश्व के इस्पात निर्यात में इसकी हिस्सेदारी संबंधी आंकड़े नीचे दिए गए हैं:-

वर्ष	निर्यात (सेमीज + तैयार इस्पात) (एमटी)		
	विश्व^*	भारत#	भारत का शेयर%*
2023	434.7	7.8	1.8
स्रोत: ^वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन (डब्ल्यूएसए); #संयुक्त संयंत्र समिति; *अनंतिम			

(ग) इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है। सरकार इस्पात क्षेत्र के विकास हेतु अनुकूल नीतिगत वातावरण सृजित कर एक सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करती है। देश में इस्पात के उत्पादन और खपत में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:-

i. सरकारी अधिप्राप्ति हेतु मेड इन इंडिया इस्पात को बढ़ावा देने के लिए घरेलू स्तर पर विनिर्मित लौह एवं इस्पात उत्पाद (डीएमआईएंडएसपी) नीति का कार्यान्वयन।

ii. सरकार ने देश में 'विशेष इस्पात' के विनिर्माण को बढ़ावा देने और पूंजीगत निवेशों को आकर्षित कर आयात को कम करने के लिए विशेष इस्पात हेतु उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना शुरू की है। पीएलआई योजना के तहत विशेष इस्पात हेतु 29,500 करोड़ रुपए का प्रत्याशित अतिरिक्त निवेश और विशेष इस्पात के लिए लगभग 25 मिलियन टन (एमटी) की अतिरिक्त क्षमता का सृजन अपेक्षित है।

iii. देश में इस्पात के उपयोग, इस्पात की समग्र मांग और इस्पात क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने के लिए रेलवे, रक्षा, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, आवासन, नागर विमानन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, कृषि एवं ग्रामीण विकास क्षेत्रों सहित संभावित उपयोगकर्ताओं के साथ और अधिक सहभागिता के साथ मेक इन इंडिया पहल और प्रधानमंत्री गति-शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान।

iv. इस्पात बनाने हेतु अधिक अनुकूल शर्तों पर कच्चे माल की उपलब्धता को और अधिक अनुकूल बनाने के लिए अन्य देशों के अलावा मंत्रालयों व राज्यों के साथ समन्वय करना।

v. घरेलू स्तर पर उत्पन्न स्क्रैप की उपलब्धता को बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति को अधिसूचित करना।

vi. गैर-मानकीकृत इस्पात के विनिर्माण एवं आयात को रोकने तथा बड़े पैमाने पर आम जनता को गुणवत्तापूर्ण इस्पात उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए 145 इस्पात गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों को अधिसूचित करना।

*****